वर्ष 4 अंक 12 दिसम्बर 1982 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू यूनियनें ध्यान दें

सीटू के सेक्रेटेरियट ने 20 अक्टूबर को सम्पन्न अपनी बैठक में 1983 में होने वाले सीटू के पांचवें सम्मेलन की तैयारियों पर विचार किया.

बंगलौर में पिछली जुलाई में सम्पन्न वर्किंग कमेटी के फैसले के अनुसार डेलीगेटों की संख्या उस सदस्यता के आधार पर तय की जाएगी जिसके लिए चन्दा प्राप्त हो चुका है और इस संख्या की अधिकतम सीमा 2,500 है. रिकार्ड देखने से पता चलता है कि बहुत सी यूनियनों ने मद्रास में सम्पन्न सीटू के पिछले सम्मेलन के बाद से अपनी सम्बद्धता शुल्क अदा नहीं किया है. अब तक दिए गए सम्बद्धता शुल्क के आधार पर डेलीगेटों की संख्या तय करना कठिन होगा इसलिए यूनियनों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना सम्बद्धता शुल्क का भुगतान करें और 31 दिसम्बर 1981 तक की अपनी रिटर्न भेजें.

सेक्रेटेरियट ने फैसला लिया कि सभी यूनियनें 31 दिसम्बर 1982 तक उपरोक्त निर्देशों का पालन करें, नहीं तो शुल्क का भुगतान न करने और सालाना रिटर्न की प्रतिलिपि न भेजने से सीटू के पांचवें सम्मेलन में उनके भाग लेने में दिक्कत आ सकती है. सभी यूनियनों को इस फैसले से अवगत करा दिया जाए और वे इसका पालन करें ताकि हर राज्य का डेलीगेशन 'कोटा' 31 दिसम्बर 1982 तक तय किया जा सके और अन्य तैयारियां की जा सकें. □

कामरेड लियोनिद ब्रेझनेव

बहुत ही दुख के साथ भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू) सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, कॉमरेड लियोनिद इलिच ब्रेझनेव को, जिनका 10 नवम्बर को निधन हो गया, श्रद्धांजलि देता है. शांति के लिए संघर्ष के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान ने उनको विश्व की शांति-प्रेमी जनता का प्रिय बना दिया था.

जब अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी विश्व को नाभिकीय नरसंहार के कगार पर लाते हुए पगली-अस्त्र-दौड़ में व्यस्त थे, उस समय कॉमरेड ब्रेझनेव ने नाभिकीय अस्त्र परीक्षण को खत्म करने, युद्धनीतिक अस्त्रों को सीमित करने, आदि, के लिए कई प्रस्ताव पेश किये. उन्होंने घोषणा की कि सोवियत संघ नाभिकीय अस्त्रों को इस्तेमाल करने में सर्वप्रथम नहीं होगा. जब साम्राज्यवादियों ने इन सब प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और सार्वभौमिक प्रभुत्व के इरादे से युद्धोन्माद पैदा करना जारी रखा, उस समय उन्होंने शांति को बनाए रखने के एक कदम के रूप में सैन्यशक्ति में समानता रखते हुए सोवियत संघ की प्रतिरक्षात्मक तैयारियों के लिए कदम उठाए. प्रसाधनों को प्रतिरक्षा के लिए मोड़ने के लिए इस तरह बाध्य होने के बावजूद, सोवियत संघ उनके मार्गदर्शन में सोवियत जनता के हित में समाजवादी संरचना में चहुमुखी प्रगति करता रहा.

उनके नेतृत्व में सोवियत संघ ने विकासशील देशों को अपनी अर्थ-व्यवस्था के निर्णाण में और साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों को पछाड़ने में सहायता दी. भारत की जनता 1970 में भारत-सोवियत मित्रता संधि पर, जिसने भारत को बंगलादेश में मुक्ति संघर्ष की सहायता करने के लिए योग्य बनाया था, हस्ताक्षर किये जाने में उनके योगदान को याद करती है.

उन्होंने यूरो-कम्युनिज्म की भिन्नप्रकृति की अवधारणाओं के खिलाफ मार्क्सवाद-लेनिनवाद की रक्षा की और समाजवादी खेमें में एकता के लिए कोशिशें कीं. विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन ने उनके निधन से एक असाधारण नेता खो दिया है.

सीटू एक बार फिर उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करती है और सोवियत संघ के मजदूर वर्ग व जनता को अपनी हृदय-विदारक संवेदना भेजती है. □

अखिल भारतीय टेक्सटाइल हड़ताल : 21 दिसम्बर

नाविकों द्वारा तीन दिन की हड़ताल

वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया की टूटीकोरिन में 6 व 7 सितंबर को संपन्न वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक भारतीय नाविक अपने 9-सूत्री मांगपत्र के समर्थन में 25 से 27 नवंबर तक 72 घंटे की लगातार हड़ताल करेंगे. इस बैठक में सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति हाजिर थे.

नाविकों की मांगें हैं : रोजगार की आकस्मिक प्रणाली का खात्मा और पूरे साल भारतीय नाविकों को रोजगार की गारंटी, 'साइन-आफ से साइन-आन' तथा 700 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, आई एल ओ की सिफारिश के अनुसार 115 स्टर्लिंग-पाउंड न्यूनतम बेसिक वेतन, दोहरी चिकित्सा परीक्षण का खात्मा व परिवार चिकित्सा सहायता की बहाली, एम. एस. कानूनों व समझौतों में से नाविक विरोधी धाराओं का खात्मा, गुप्त मतदान द्वारा यूनियनों को मान्यता, वार्षिक वेतन वृद्धि व 20 प्रतिशत बोनस, जहाजरानी उद्योग का राष्ट्रीयकरण. इसके अलावा एडमिरल एस. एम. नंदा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की गयी है.

भारतीय नाविकों ने लंबे समय से लगातार आंदोलन के दौरान कई हड़ताली कार्यवाहियां की हैं और सीटू के उपाध्यक्ष व पश्चिम बंगाल के मुख्य-मंत्री ज्योति बसु, की मध्यस्थता से कुछ समझौते हुए हैं. लेकिन भारत सरकार व शिप-मलिकान ने उन्हें लागू नहीं किया, और उनपर, विदेशी बंदरगाहों सहित, दमन शुरू कर दिया गया. भारत सरकार व शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया ने न्यूजीलैंड की टावरंगा पोर्ट पर कार्यरत नाविकों को धमकी दी क्योंकि उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान एक शिप के प्रस्थान में एक दिन की देर करा दी थी.

इन हालात में फेडरेशन ने 15 अक्तूबर को सभी शिपिंग कंपनियों, भारत व विदेशों की बंदरगाहों के अधिकारियों, तथा भारत सरकार को हड़ताल का नोटिस दे दिया था. फेडरेशन के साथ साथ फारवर्ड सीमेंस यूनियन आफ इंडिया (सीटू) ने भारत व विदेशों में कार्यरत नाविकों की सभी ट्रेड यूनियनों से कहा है कि वे हड़ताल में भाग लें. विभिन्न व्यापारी जहाजों व कलकत्ता के मैरीन हाउस पर नाविक हड़ताल की सफलता के लिए हर रोज प्रदर्शन कर रहें हैं. □

बंबई कपड़ा हड़ताल पर सरकारी प्रस्ताव की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा निंदा

राष्ट्रीय अभियान समिति की 1 नवंबर को नई दिल्ली में संपन्न एक बैठक ने बंबई के ढाई लाख मजदूरों की साढ़े नौ महीने लंबी हड़ताल का समाधान करने के लिए पेश किए गए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों की कड़ी निंदा की है. महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का प्रस्ताव दरअसल बंबई के मिल मालिकान का प्रस्ताव है जैसा कि यह इससे साबित होता है कि उन्होंने इसका तहेदिल से स्वागत किया है.

सीटू के महासचिव पी राममूर्ति ने बैठक की अध्यक्षता की.

काफी पहले बंबई के कपड़ा मजदूरों ने 30 रुपये अंतरिम राहत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. बोनस की अदायगी व बकाया वेतनों की अदायगी का प्रस्ताव दरअसल कानूनन है और यह अदायगी हर हालत में मालिकान ने करनी है. नया प्रस्ताव केवल अग्रिम राशि में बढ़ोतरी है जिसे मजदूरों को वापस करना पड़ेगा. इस राशि पर मालिकान को कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस बारे में बैंक मालिकान की सहायता करेंगे.

बैठक ने यह नोट किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हड़ताल में हिस्सा लेने वाली ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत द्वारा कोई समझौता करने की बजाए मालिकान के प्रतिनिधियों के साथ बात करने के बाद एकतरफा समझौता खोजने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार लंबी हड़ताल के परिणामस्वरूप मजदूरों की भारी आर्थिक दिक्कतों का फायदा उठाने की उम्मीद में है.

राष्ट्रीय अभियान समिति ने बंबई के कपड़ा मजदूरों को प्रस्ताव को रद्द करने और केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ दृढ़ निश्चयी संघर्ष करने के लिए बधाई दी.

बैठक ने सरकार से मांग की कि यह हड़ताल में हिस्सा लेने वाली यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करें ताकि जल्दी से जल्दी एक उचित समझौता हो सके.

राष्ट्रीय अभियान समिति ने देश के मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वह बंबई के कपड़ा मजदूरों के साथ अपनी एकजुटता को और मजबूत करें ताकि बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए सरकार मजबूर हो जाए. □

धनबाद जिला कोआर्डिनेशन कमेटी ने चार ट्रेड यूनियन विरोधी विधेयकों के खिलाफ 26 सितंबर को एक सम्मेलन आयोजित किया ताकि इन विधेयकों के खिलाफ आंदोलन को जारी रखने के लिए मजदूरों को लामबंद किया जा सके. सम्मेलन में बिहार प्रेस विधेयक, इस्माइली दमन, रेलवेकर्मियों व शिक्षकों के तबादले, एलआईसी को विभाजित करने के कदम, कोयला मजदूरों की 8 नवंबर की हड़ताल, आदि 5 पर कई प्रस्ताव अपनाए गये. □

दिसम्बर के अन्त में हड़ताल

राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा 12 व 13 अक्तूबर को आयोजित हैदराबाद सम्मेलन के आह्वान के समर्थन में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने बी पी ई को खत्म करने तथा सामूहिक सौदेबाजी द्वारा वेतन-वार्ताओं पर समझौता करने की मांग करते हुए 8 नवम्बर को अखिल भारतीय दिवस मनाया. इस दिन बिल्ले लगाए गए, और प्रतिष्ठानों के सामने प्रदर्शन, रैलियां व गेट मीटिंगें तथा धरने आयोजित किए गए.

साथ ही इस दिन कोयला उद्योग के हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त की गयी. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों व हड़ताली कोयला मजदूरों के समर्थन में निजी क्षेत्र के मजदूरों व कर्मचारियों ने भी एकजुटता व्यक्त की. उन्होंने उत्पादकता से जुड़े वेतन की निंदा की और यह वर्ष खत्म होने से पहले मांग-पत्रों पर समझौतों की मांग की.

प्राप्त खबरों के मुताबिक बंगलौर व हैदराबाद स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों ने संयुक्त प्रदर्शन, जुलूस व धरने आयोजित किए. बैंक, एल आई सी व अन्य उद्योगों के कर्मचारियों ने भी विभिन्न स्थानों पर रैलियां की.

कोयला मजदूरों की हड़ताल ने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का हौसला बढ़ाया तथा जुझारू संघर्षों का रास्ता तैयार किया है. सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल में, जिसमें कोयला उद्योग भी शामिल होगा, ज्यादा से ज्यादा मजदूर शामिल होंगे तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को खत्म करने की सरकार की नीति तथा इस द्वारा मजदूरों की एकता को कम करके आंकने के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देंगे.

राष्ट्रीय अभियान समिति की बैठक

2 नवम्बर को सम्पन्न इसकी बैठक में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के 64 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस बैठक का विशेष महत्व इसलिए भी था क्योंकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल की तारीख तय की जानी थी. राष्ट्रीय फेडरेशनों के नेताओं की राय एकसमान थी और उनका विचार था कि क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ बातचीत करने का सरकार का कोई मूड नहीं नजर आता, बल्कि दूसरी ओर इसने मजदूरों पर, खासतौर से सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों पर हमले तेज कर दिए हैं, क्योंकि यह आई एम एफ व विश्व बैंक के इशारों पर नाच रही है और क्योकि सार्वजनिक क्षेत्र के समझौते दिसम्बर में खत्म हो रहे हैं, इसलिए हड़ताल भी दिसम्बर में ही होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हड़ताल की पूर्ण तैयारी होनी चाहिए. इसलिए राष्ट्रीय अभियान समिति की बैठक महीने के अन्त में फिर होगी ताकि दिसम्बर के अन्त में होने वाली हड़ताल की तारीख तय की जा सके. इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अभियान और तैयारी आन्दोलन तेज किया जाएगा. साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी हड़ताल के दिन एकजुटता कार्यवाहियां करेंगे.

19 जनवरी

बैठक ने यह भी फैसला किया कि 19 जनवरी 1983 को, पहली अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल के दिन, सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों तथा काले विधेयकों के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए रैलियां, प्रदर्शन, धरने आदि आयोजित किए जाएंगे.

अखिल भारतीय सम्मेलन

राष्ट्रीय अभियान समिति की गतिविधियों का जायजा लेने के लिए और श्रम-विरोधी नीतियों व कीमत वृद्धि के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए 4 जून 1981 के बम्बई सम्मेलन की तरह का एक और सम्मेलन करने का भी फैसला लिया गया. इसका उद्देश्य होगा कांग्रेस(आई) के अधिनायकवाद के बढ़ते खतरे का कारगर प्रतिरोध करने के लिए संगठित मजदूरों, किसानों व खेत-मजदूरों के बड़े हिस्सों को एक मंच पर लामबंद करना. आगामी सम्मेलन अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किए गए नाभिकीय युद्ध के बढ़ते खतरे के खिलाफ शांति के लिए एक व्यवस्थित ढंग से संघर्ष शुरू करने के लिए मजदूरों को लामबंद करने के कार्य पर ध्यान देगा. □

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा मांग दिवस : बोनस सप्ताह

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने 21 सितम्बर को पूरे देश में मांग-दिवस मनाया. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के समान वेतन, अंतरिम राहत, सबको बोनस, जुलाई माह से देय मंहगाई-भत्ते की अदायगी तथा बहुत दिनों से विचाराधीन अन्य मांगों के लिए इस दिवस का आह्वान कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज एण्ड वर्कर्स तथा ऑल इण्डिया डिफेंस एम्प्लाईज फेडरेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था. विभिन्न राज्यों में रैलियों, जुलूसों तथा प्रदर्शनों का आयोजन करके यह दिवस मनाया गया और विभागीय अधिकारियों को मांगों के साथ ज्ञापन दिए गए.

(शेष पृष्ठ सात पर)

जनसमुदाय शिक्षा पर कार्यशाला

नई दिल्ली में 4 से 6 नवंबर को "श्रमिक शिक्षा के साथ जनसमुदाय शिक्षा का एकीकरण" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हुई. इसे अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) तथा सेंट्रल बोर्ड आफ वर्कर्स एजुकेशन (सीबीडब्लूई) ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था. सीटू की ओर से इसकी जनरल काउंसिल के सदस्य पी. के. गांगुली ने भाग लिया.

इसका उद्देश्य था सरकार के सामने जनसंख्या में भारी वृद्धि की समस्या जिसके कारण विकास योजनाओं में बाधाएं आ रही हैं. इसका इरादा सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का सहयोग लेना था. केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री मोहसिना किदवई ने उद्घाटन करते हुए कहा कि जनसंख्या में जो अब 68 करोड़ है भारी वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो गयी हैं जिसके कारण जनता की उन्नति व जीवनस्तर पर असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मेहनतकश पुरुषों व महिलाओं में 'लघु परिवार' की बात को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए. सीबीडब्लूई के निर्देशक, आई एल ओ व नेशनल इंस्टीयूट आफ हैल्थ व फैमिली वेलफेयर के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरान और अन्य वक्ताओं ने एक सुर से यही कहा.

पी.के. गांगुली ने कहा कि सीटू परिवार नियोजन का समर्थन करती है लेकिन साथ ही इसकी यह राय है कि देश की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से अलग करके जनसंख्या की समस्या को नहीं देखा जा सकता. इतिहास यह बताता है कि बेहतर जीवनस्तर, बेहतर शिक्षा, और सामंती दृष्टिकोण से महिलाओं के छुटकारे के द्वारा ही परिवार नियोजन को सफल बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि आज 70 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत जनसंख्या सामंती शिकंजे में है, 75 प्रतिशत की आधुनिक चिकित्सा तक पहुंच नहीं है, और महिलाओं में जिनकी शिशुजन्म के मामलों में समान राय होनी चाहिए, निर्क्षरता व पिछड़ेपन को तो बयान ही नहीं किया जा सकता. मुसलमानों व इसाइयों जैसे अल्पसंख्यकों के परिवार नियोजन के खिलाफ धार्मिक विचार हैं और धर्मनिर्पेक्ष तरीके से उनमें इन विचारों के खिलाफ शिक्षा अभियान नहीं चलाया गया है. जीवन स्तर बेहतर बनाए बिना परिवार नियोजन आम जनता में नहीं पहुंच सकता. इसलिए सरकार की वैकल्पिक आर्थिक नीति की जरूरत है जिससे सम्पूर्ण बदलाव लाया जा सके, और परिवार नियोजन को कामयाब बनाया जा सके.

अधिवेशन का समापन करते हुए सीबीडब्लूई के निदेशक ने कहा कि इस पर एकमत है कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जनसंख्या की समस्या को अलग नहीं किया जा सकता. □

कपड़ा उद्योग में एकजुटता हड़ताल

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने 25 नवम्बर को जारी एक बयान में कपड़ा उद्योग की सभी यूनियनों व फेडरेशनों का आह्वान किया है कि वे बम्बई के 2.5 लाख कपड़ा मजदूरों के संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए 21 दिसम्बर को इस उद्योग में अखिल भारतीय हड़ताल करें ताकि शीघ्र वार्ता द्वारा समझौता करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जा सके. □

मंहगाई के आंकड़े

आधार 1960 : 100

राज्य/केन्द्र	1982		
	जून	जुला.	अग.
बिहार			
जमशेदपुर	448	451	468
झारिया	440	445	464
कोडरमा	501	515	528
मोंघाइर	514	522	531
नोआमुंडी	457	444	475
गुजरात			
अहमदाबाद	472	479	494
भावनगर	467	480	502
हरियाणा			
यमुनानगर	505	512	524
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	503	501	512
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	483	489	512
भोपाल	496	512	536
ग्वालियर	490	504	519
इन्दौर	514	522	540
महाराष्ट्र			
बम्बई	488	496	506
नागपुर	482	496	519
शोलापुर	500	513	523
पंजाब			
अमृतसर	472	485	496
राजस्थान			
अजमेर	493	503	513
जयपुर	511	518	530
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	456	470	490
सहारनपुर	480	498	504
वाराणसी	510	516	534
पश्चिम बंगाल			
आसनसोल	471	474	482
कलकत्ता	437	439	450
दार्जीलिंग	389	396	405
हावड़ा	420	427	431
जलपाईगुड़ी	377	386	404
रानीगंज	457	463	466
दिल्ली	500	506	521
भारत	470	478	488

इस्पात वेतन-वार्ताओं में कोई प्रगति नहीं

मजदूरों में यह भ्रम पैदा करने के लिए कि समझौता वार्ताएं ठीक ठाक हो रही हैं इस्पात प्रबंधकों की एनजेसीएस की बैठकें जल्दी जल्दी बुलाने की नीति से अभी तक कोई हल नहीं निकला है. 29 अक्तूबर से 2 नवंबर तक की 5 दिवसीय बैठक व 9 से 11 नवंबर की 3 दिवसीय बैठक से बातचीत में केवल नाम मात्र की ही प्रगति हुई है.

प्रबंधकों ने प्रमुख मुद्दों पर उचित लाभ न देने का फैसला किया है जबकि ये तुलनात्मक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव पेश कर रहे हैं. इस चालाकी को समझते हुए ट्रेड यूनियनों ने भी प्रमुख मुद्दों पर जोर दिया है और इस्पात मजदूरों की असल उम्मीदों के साथ प्रबंधकों का सामना किया है.

मजदूर दल ने विभिन्न घटकों से विचार विमर्श करके अकुशल मजदूर के लिए कुल न्यूनतम वेतन 935 रूपये और रू. 2.25 पै. मूल्य सूचकांक में प्रतिबिंदु वृद्धि की दर से मंहगाई भत्ते की मांग की. प्रबंधकों ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि इतना न्यूनतम वेतन उनकी क्षमता से बाहर है और मंहगाई भत्ते की दर राष्ट्रीय स्तर पर तय की जाएगी. प्रबंधकों का अभी तक 50 रूपये न्यूनतम गारंटिड लाभ व नये वेतनमान पर एक वृद्धि देने का वही पुराना प्रस्ताव है. नए प्रस्ताव पर जोर देने पर प्रबंधकों ने कहा कि ट्रेड यूनियनें 'उचित निम्न स्तर' पर आएं ताकि प्रबंधक नया प्रस्ताव रख सकें. यह सीटू व अन्य यूनियनों को स्वीकार्य नहीं है.

इस्पात उद्योग में ठेका मजदूरों की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और प्रबंधक इस संबंध में कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं. कुछ ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का कहना था कि इस मुद्दे पर पहले मजदूर दल में बात करके ही प्रबंधकों से बात की जाय इसलिए एनजेसीएस में इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया. फिर भी सीटू प्रतिनिधियों ने बैठक में अपनी स्थिति बतायी और ठेका मजदूरों के कार्य व निर्वाह के हालात में सुधार पर जोर दिया.

नए वेतन ढांचे पर विस्तार से बहस हुई. वेतन ढांचा तय करने से पहले जो मुद्दे तय होने हैं वे इस प्रकार हैं : (1) हर ग्रेड के लिए वृद्धि की दर, (2) हर वेतनमान का आरंभ व अंत, (3) हर वेतनमान का समय. इनमें से किसी पर भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. प्रबंधक वेतनमानों की संख्या बढ़ाना चाहते थे लेकिन मजदूर दल ने इसे नामंजूर कर दिया. न्यूनतम व अधिकतम वृद्धि की दरें 11 व 55 रूपये निर्धारित की गयी हैं लेकिन प्रबंधक एस-1 वेतनमान में केवल एक ही स्टेप चाहते थे. ट्रेड यूनियनों ने दो स्टेप की मांग की. जब प्रबंधक जिद्दी थे तो इंटक ने सुझाव दिया कि जब एस-1 ग्रुप के मजदूर वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचे तो उनकी अपने आप पदोन्नति होनी चाहिए. प्रबंधकों ने इसे भी नामंजूर कर दिया. हालांकि एस-2 से एस-9 वेतनमानों की वृद्धि दरें तय हो गई हैं फिर भी उपरोक्त मामले में रूकावट जारी है. हर वेतनमान के समय और उसके अधिकतम स्तर पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका क्योंकि प्रबंधक 1,500 रूपये से ज्यादा अधिकतम बेसिक वेतन नहीं देना चाहते.

पेंशन योजना पर भी प्रबंधकों ने अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा है. यह मुद्दा अभी बातचीत तक ही सीमित है और प्रबंधक इसमें कोई खास रूचि नहीं ले रहे हैं. लाइफ कवर योजना के बारे में हालांकि प्रबंधकों ने राशि को 11,000 से बढ़ाकर 15,000 रूपये स्वीकार कर लिया है लेकिन इसका संबंध ग्रेच्युटी से खत्म करना उन्होंने अभी तक नहीं स्वीकारा है.

इंसेटिव योजना व मकान किराया रिकवरी के सवाल पर निष्कर्षों के केवल मसौदे को ही एनजेसी एस अंतिम रूप दे पायी है. एल टी सी के सवाल पर प्रबंधकों ने उन मजदूरों के लिए जिनका घर इस्पात प्लांटों के नजदीक है 500 किलोमीटर हर मार्ग के लिए देने का प्रस्ताव रखा. ट्रेड यूनियनों ने हर मार्ग के लिए 750 किलोमीटर का प्रस्ताव रखा जिसे प्रबंधकों ने स्वीकार नहीं किया लेकिन कहा कि यदि यह पति, पत्नि व दो बच्चों तक ही सीमित हो तो वे इस पर विचार कर सकते हैं. ट्रेड यूनियनों ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे परिवार की सीमा नहीं लगाना चाहती थीं.

इस प्रकार प्रगति केवल नाम के लिए ही रही. इस्पात वार्ताओं में मजदूरों को बीपीई की पर्दे के पीछे की कार्यवाहियां साफ दिखाई पड़ने लगी हैं.

खबरों के मुताबिक 8 नवंबर को बीपीई के निर्देशों के खिलाफ व कोयला मजदूरों के समर्थन में इस्पात मजदूरों ने प्रतिरोध दिवस मनाया. स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया के उपाध्यक्ष एम. के. पंधे की अध्यक्षता में फेडरेशन के पदाधिकारियों की 31 अक्तूबर को नयी दिल्ली में सम्पन्न बैठक में प्रबंधकों पर दबाव डालने के लिए इस्पात मजदूरों का प्लांट-स्तरीय आंदोलन तेज करने का फैसला लिया गया. इन पदाधिकारियों की अगली बैठक कलकत्ता में होगी जिसमें प्रचार का जायजा लिया जाएगा और राष्ट्रीय अभियान समिति के फैसले के मुताबिक एक दिन की हड़ताल के लिए आंदोलन को तेज करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

एनजेसीएस की अगली बैठक 8-10 दिसंबर को होगी. □

महिला प्रतिनिधियों की आई एल ओ के सहायक निदेशक से भेंट

विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने 22 अक्टूबर को नयी दिल्ली में आई एल ओ की सहायक निदेशक तथा आई एल ओ के समानता विभाग की मुखिया, जिसके तहत 'महिला कामगार प्रश्न' कार्यालय तथा 'रोजगार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास व समानता का अधिकार शाखा' आती हैं, मैडम एंटोइनेट बेगुइन से भेंट की. आल इन्डिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन (सीटू) की ओर से विमल रणदिवे ने उनसे भेंट की.

महिला प्रतिनिधियों ने उनसे कई विषयों पर बात-चीत की जैसे समान पारिश्रमिक कानून लागू न किया जाना, तकनीकी परिवर्तन व कामगार महिलाओं पर उनके प्रभाव, महिला प्रशिक्षण के लिए नाममात्र की सुविधा, निर्माण व असंगठित उद्योगों में कामगार महिलाएं. उन्होंने देश में गहराते आर्थिक संकट, बढ़ती कीमतों, जबरदस्त गरीबी व बढ़ती बेरोजगारी पर भी चर्चा की. मैडम बेगुइन ने कहा कि भारत सहित कई देश आई एल ओ की विभिन्न कनवेंशनों को अपनाते नहीं हैं या अपनाकर उन्हें लागू नहीं करते हैं. प्रतिनिधियों ने उनसे अनुरोध किया कि वे कामगार महिलाओं की समस्याओं में हस्तक्षेप करें. □

महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ रैली

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ हिसार (हरियाणा) में 1 नवम्बर को एक भारी रैली संपन्न हुई. बड़ी संख्या में महिलाओं, मजदूरों, छात्रों, आदि, ने रैली में भाग लिया. दहेज के कारण मौतों, बलात्कार, अपहरण व महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती वारदातों के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने पुलिस की भी निंदा की क्योंकि वह स्वयं भी इस तरह के अत्याचार में शामिल होती है. उन्होंने सरकार से मांग की कि वह दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें.

रैली को सम्बोधित करते हुए आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन (सीटू) की सचिव विमल रणदिवे ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार सामंती समाज की निशानी है और एक बड़ी सामाजिक बुराई है. सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा निर्क्षरता व पिछड़ेपन से महिलाओं के छुटकारे के लिए संघर्ष के साथ साथ ही इस बुराई के खिलाफ संघर्ष भी करना होगा. भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण गरीबी, निर्क्षरता, बेरोजगारी व अपराध बढ़े हैं तथा नैतिक मूल्य कम हुए हैं. इस बारे में खास निशाना महिलाएं ही हैं. इसलिए महिलाओं को साथ लेकर जनता व मजदूरों को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जुझारू संघर्ष करने के लिए एकजुट होना होगा. उन्होंने बताया कि कोआर्डिनेशन कमेटी ने आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमैन एसोसिएशन व अन्य महिला संगठनों के साथ मिलकर इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है और उन्होंने जनता का आह्वान किया कि वह संघर्षों को पूरा समर्थन दें. □

शिक्षकों का संघर्ष

विभिन्न महिला कालेजों के शिक्षकों ने यू जी सी-वेतन मानों, सेवा सुरक्षा, बेहतर सेवा शर्तों, आदि की मांग करते हुए सक्रिय आंदोलन शुरू कर दिया है. खासतौर से निजी अल्पसंख्यक कालेजों में महिला शिक्षकों की हालत निंदनीय है. मालिकान इन कालेजों को व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरह चलाते हैं न कि शिक्षण-संस्थानों की तरह और मनगढ़ंत बहानों पर इन शिक्षकों को निकालने में हिचकिचाते नही.

मद्रास में महिलाओं के एस आई ई टी कालेज के शिक्षकों ने 1979 में एसोसिएशन आफ यूनिवर्सिटी टीचर्स (ए यू टी) के नेतृत्व में यू जी सी-वेतन मानों, आदि, की मांग करते हुए प्रबंधकों को एक ज्ञापन दिया था. उनकी मांगों का समर्थन करते हुए छात्रों व गैरशिक्षण स्टाफ ने भी एक संयुक्त ज्ञापन दिया था. उसके बाद प्रबन्धकों ने कालेज बंद कर दिया. शिक्षकों ने क्रमिक भूखहड़ताल की, चार शिक्षक, दो गैर-शिक्षण स्टाफ व दो छात्रों ने लगातार भूखहड़ताल की. फिर ए यू टी के सदस्यों पर हमले व उत्पीड़न तेज हुए और दूसरी बार कालेज बंद हुआ तथा कई शिक्षक गिरफ्तार हुईं. सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही. आन्दोलन तेज़ होने पर प्रबन्धकों को कालेज मार्च 1980 में खोलना पड़ा. अब इसके प्रबन्धक इसे 5-सितारा होटल में बदलना चाहते हैं. इस वजह से उन्होंने छात्रों की संख्या कम करनी शुरू कर दी है और 1981-82 में 1200 की बजाए 400 छात्र दाखिल करके 35 शिक्षकों को फालतू घोषित कर दिया. इस साल जून महीने में प्रथम वर्ष स्नातकीय कोर्स ही खत्म कर दिया गया और 185 के स्टाफ में से 123 को बाहर निकाल दिया गया.

शिक्षकों ने आन्दोलन तेज कर दिया है और तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को 15 हजार हस्ताक्षर-युक्त एक जनज्ञापन दिया गया कि सरकार इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करे. □

टी यू आई टेक्सटाइल का सम्मेलन

ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल आफ टेक्सटाइल, क्लोदिंग, लैदर एंड फर वर्कर्स का 8वां सम्मेलन 20 से 24 सितम्बर को बर्लिन, पूर्वी जर्मनी, में सम्पन्न हुआ. विभिन्न देशों के 140 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया. आल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) की ओर से इसकी अध्यक्ष लक्ष्मी सहगल ने इसमें हिस्सा लिया.

सम्मेलन में हुई बहस से पता चलता है कि सभी पूंजीवादी देशों के कपड़ा व जूट उद्योग संकट में हैं और मजदूरों को कम वेतन, तालाबंदी व बढ़ती बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है. आस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रीस, इटली, कोलम्बिया, टर्की, फिलिपाइन्स, जापान, आदि के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके देश की सरकारें नीति मामलों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सामने घुटने टेकती हैं जिसके फलस्वरुप मजदूरों पर भारी दमन, तालाबन्दी आदि होती है. स्वचालन व मशीनीकरण से स्थिति बिगड़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है. उन्होंने मजदूरों के बढ़ते संघर्षों पर प्रकाश डाला.

लक्ष्मी सहगल ने पश्चिम बंगाल के जूट मजदूरों की गौरवमयी हड़ताल पर प्रकाश डाला और बताया कि भारत सरकार की मदद से जूट मालिकान ने किस तरह हमले किए तथा 16 मिलों को बन्द कर दिये जिसने 60 हजार मजदूरों पर असर डाला. ये मालिकान समझौतों का उल्लंघन कर रहे हैं और ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को उत्पीड़ित कर रहे हैं. औद्योगिक बीमारी के नाम पर ये सरकार से धन प्राप्त करते हैं और दूसरे उद्योगों में लगा देते हैं. उन्होंने बताया कि आई एल ओ के नियमों के मुताबिक सुविधाएं देने से इंकार किया जाता है. उन्होंने कामगार महिलाओं के शोषण का जिक्र किया और बताया कि वे संगठित होकर संघर्षों में शामिल हो रही हैं.

बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल में प्रतिनिधियों ने काफी दिलचस्पी ली और प्रधानमंत्री के मजदूर वर्ग के प्रति घरेलू नीति पर टोकाटाकी की क्योंकि उन दिनों प्रधान मंत्री की सोवियत यात्रा के दौरान उन्हें अफगानिस्तान, कम्पूचिया, पी. एल. ओ. आदि के बारे में काफी प्रचार मिल रहा था. हड़ताली कपड़ा मजदूरों के साथ एकजुटता एक प्रस्ताव में व्यक्त की गयी.

समाजवादी देशों के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके देशों में ट्रेड यूनियनें अप्रेंटिसों को ज्यादा भत्ते, औद्योगिक बीमारी व रोकथाम पर अनुसंधान, कार्यभार में कमी, चिकित्सा सुविधा सुधार आदि के कार्यों में लगी हैं. इन देशों में महिलाओं को 26 सप्ताहों की प्रसूति छुट्टी और दूसरे बच्चे के बाद एक साल की छुट्टी दी जाती है ताकि बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताया जा सके.

सम्मेलन ने शांति पर, अमरीकी हथियार दौड़, पूंजीवाद व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हानिकारक परिणामों के खिलाफ ट्रेड यूनियन कार्यों व वैकल्पिक आर्थिक नीति पर प्रस्ताव अपनाए.

सम्मेलन का समापन करते हुए टी यू आई के महासचिव जान क्रिज ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे पूंजीवादी देशों में संकट व विकासशील देशों में बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ के खिलाफ और शान्ति व निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करें. □

टी यू आई मेटल का सम्मेलन

ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल आफ मेटल का 9वां सम्मेलन मास्को में 20 से 24 सितम्बर को संपन्न हुआ. 70 देशों के 116 संगठनों के 263 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया. स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया के संयुक्त महासचिव अर्धेंदु दक्षी ने फेडरेशन की ओर से हिस्सा लिया.

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए टी यू आई मेटल के अध्यक्ष राइनहार्ड सोम्बर ने कहा कि पूंजीवादी देशों में जहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विज्ञान व तकनीकी की प्रगति के आदेश देती हैं, वैज्ञानिक क्रांतियों के लाभ मजदूरों के हितों के खिलाफ जा रहे हैं. महासचिव अलैन स्टर्न ने रिपोर्ट में पूंजीवादी संकट व युद्ध-तैयारियों का जिक्र करते हुए इनके खिलाफ एकजुट संघर्ष का आह्वान किया.

अर्धेंदु दक्षी ने भारत में इस्पात व ठेका मजदूरों की दशा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश में सरकार की अधिनायकवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष तेज होते जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की वामपंथी सरकारों के प्रगतिवादी चरित्र की चर्चा की गयी. □

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी...

(पृष्ठ तीन से आगे)

कर्मचारियों ने आन्दोलन के दूसरे दौर में 11 से 15 अक्टूबर तक पूरे देश के पैमाने पर बोनस सप्ताह मनाया. राज्यों में रात और दिन धरनों तथा क्रमिक अनशनों का आयोजन किया गया. राजधानी दिल्ली में प्रति दिन बोट क्लब पर प्रदर्शन करके बोनस सप्ताह मनाया गया. केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं तथा संसद-सदस्यों ने रैलियों को सम्बोधित किया. □

न्यूनतम वेतन दिवस : 5 जनवरी

सीटू ने नई दिल्ली में 7 नवम्बर को एक न्यूनतम वेतन सम्मेलन आयोजित किया जिसने 500 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग करते हुए 5 जनवरी 1983 को न्यूनतम वेतन दिवस मनाने का फैसला किया. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली की सीटू यूनियनों के 150 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया. सम्मेलन ने अन्य राज्यों की यूनियनों का खासतौर से बिहार, हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर की यूनियनों का भी यह दिवस मनाने का आह्वान किया.

एक सात सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने जिसके सदस्य थे मुहम्मद इस्माइल, सांसद, सुशील भट्टाचार्य, सांसद, नृसिंह चक्रवर्ती, पी. सी. पांडे, भाग सिंह, अंजनी प्रसाद शर्मा व अवतार सिंह, सम्मेलन की कार्य वाही चलाई.

सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में पहली बार न्यूनतम वेतन निर्धारित करते समय कैदियों के खाने का उदाहरण दिया गया था. आज अनेक राज्यों में न्यूनतम वेतन कैदियों पर होने वाले खर्च से भी कम है. न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्धारित वेतन भी मजदूरों को नहीं दिए जाते और सरकार कानून के इस तरह उल्लंघन के खिलाफ कुछ नहीं करती. उन्होंने आह्वान किया कि न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष तेज करना चाहिए और भविष्य में एक दिन की हड़ताल की तैयारी करनी चाहिए.

प्रस्ताव पेश करते हुए दिल्ली के सूरजभान भारद्वाज ने 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित मापदंडों की व्याख्या की. इसने एक मजदूर की न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में आधार तय करते हुए एक मजदूर के तीन व्यस्क-सदस्यीय परिवार और प्रतिव्यक्ति 2700 कलोरी की खपत स्वीकार की थी. लेकिन सरकार ने इसे लागू करने से इंकार कर दिया. विभिन्न राज्यों में मौजूदा न्यूनतम वेतनों में कोई भी समानता नहीं है. दक्षिण क्षेत्र के सम्मेलन ने इस सम्मेलन जैसी ही मागें रखी हैं. दिल्ली, हरियाणा, कानपुर व अन्य क्षेत्रों के मजदूरों ने 500 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग करते हुए सांकेतिक हड़ताल भी की है. लेकिन जब तक सभी क्षेत्रों के मजदूर एकजुट होकर संघर्ष नही करते हैं तब तक इस मांग को स्वीकारने के लिए सरकार को मजबूर करना मुश्किल है.

बीस प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया और अपने अपने राज्यों की स्थिति पर प्रकाश डाला. उत्तर प्रदेश के मोंटेसरी स्कूलों में महिला शिक्षकों को केवल 60 रुपये मासिक वेतन मिलता है. न्यूनतम वेतन की मांग करने पर मजदूरों पर दमन ढाया जाता है. ठेका मजदूरों की दशा तो बंधुआ मजदूरों की सी ही है. यह भी पता चला कि मध्य प्रदेश सरकार जहां अपराधी मलखान सिंह पर 86 रुपये रोज खर्च करती है वहां यह न्यूनतम वेतन लागू करने से इंकार करती है.

सीटू उपाध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल, सांसद, ने सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों के बारे में बताते हुए मजदूरों का आह्वान किया कि वे न्यूनतम वेतन के लिए एक शक्तिशाली संघर्ष का निर्माण करें.

बहस का समापन करते हुए सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने कहा कि खेतमजदूरों को भी इस आन्दोलन में लामबंद किया जाना चाहिए. जब तक ऐसा नहीं किया जाता और 'काम के अधिकार' की मांग नहीं उठाई जाती तब तक आन्दोलन उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जो सरकार को जरूरी परिवर्तनों के लिए मजबूर कर सके.

मांगें

प्रस्ताव में उठाई गई मांगें इस प्रकार हैं.

500 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-100) 300 के ऊपर 1 रु० 70 पै. प्रति बिंदु वृद्धि दर से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता.

2. जहां वेतन इस स्तर से कम हैं वहां इन्हें इस न्यूनतम स्तर पर लाना.

3. सभी मजदूर न्यूनतम वेतन कानून के तहत लाए जाएं और सामूहिक सौदेबाजी द्वारा इस कानून के तहत निर्धारित वेतनों से ज्यादा वेतन पाने के अधिकार की गारंटी.

4. न्यूनतम वेतन कानून में इसके उल्लंघन के मामलों में सख्त सजाएं देने तथा सभी मामलों को उल्लंघन दर्ज किए जाने के एक महीने के भीतर निपटाने के प्रावधानों के लिए संशोधन किया जाए.

न्यूनतम वेतन दिवस

5 जनवरी को न्यूनतम वेतन दिवस मनाया जाए. और इस दिन रैलियां, धरने, प्रदर्शन, सम्मेलन, आदि आयोजित किए जाएं. इससे पहले मजदूरों से जनयाचिका पर हस्ताक्षर कराए जाएं और ये जनयाचिकाएं इस दिन राज्यों के श्रम मंत्रालय में दी जाएं. □

सफल कोयला हड़ताल

सात लाख कोयला खदान मजदूरों ने 8 नवम्बर को प्रबन्धकों व इंटक के गुंडों के हमलों का सामना करते हुए हड़ताल की. इस दिन कोल इन्डिया लिमिटेड (सी आई एल) के प्रबन्धकों तथा सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि मजदूरों की मांगें नहीं मानी गयीं तो और भी जबरदस्त संघर्ष किये जाऐंगे. अखिल भारतीय संघर्ष समिति द्वारा उठाई गई मांगें हैं : 1979 के राष्ट्रीय वेतन समझौते को लागू करना, नई जे बी सी सी आई को जिसमें इंटक का भारी प्रतिनिधित्व है खत्म करना, बी पी ई के प्रतिगामी निर्देशों का खत्म करना और कामन मांग-पत्र पर समझौता करना.

सी आई एल प्रबन्धक पहले की तरह यही कहते रहे कि "हड़ताल नाकामयाब है" और इसके परिणामस्वरूप सी आई एल के चेयरमैन बी.एल. वाडेरा को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. समाचार-पत्रों में छपी खबरों के अनुसार वह कोयला मजदूरों की हड़ताल से सुलटने में नाकामयाब रहे, तथा उन्होंने हड़ताल के बारे में, जो करीब-करीब सम्पूर्ण थी, गलत रिपोर्ट दी थी .

भ्रम में डालने की प्रबन्धकों की कोशिश

प्रबन्धकों की नीति मजदूरों के साथ टकराव की थी और हड़ताल को तोड़ने की उन्होंने हर कोशिश की. सी आई एल के चेयरमैन ने ही जे बी सी सी आई में इंटक व एच एम एस के पिट्ठू हिस्से को अधिक प्रतिनिधित्व देते हुए इसका पुनर्गठन किया था और इसने 31 अक्तूबर को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की कलकत्ता में और 4 नवम्बर को तथाकथित जे बी सी सी आई की बैठक बुलाकर मजदूरों को भ्रम में डालने की कोशिश की. लेकिन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने बैठकों को अस्वीकार कर दिया और इस तरह प्रबन्धकों के हितों की रक्षा तथा मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए केवल इंटक ही बैठकों में शामिल हुई.

हड़ताल तोड़ने के तरीके

सी आई एल ने इंटक से सांठ-गांठ करके मजदूरों पर सीधे हमले शुरू किए जिसके परिणामस्वरूप ईस्टर्न कोलफील्ड्स क्षेत्र में सीटू के दो कार्यकर्त्ताओं, जयमंगल यादव व गिरिजा सिंह, की हत्या कर दी गयी. धनबाद-झरिया कोयला क्षेत्रों में व्यवस्थित ढंग से हमले किए गए. भुरखुंडा में सी एम एस आई के नेता एन.के.पी. सिंहा सहित अनेक मजदूरों को गिरफ्तार किया गया. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स में इंटक के झंडे लगी प्रबन्धकों की जीपें मजदूरों को धमकी देती तथा हड़ताल का विरोध करने के लिए कहती घूमती रहीं. अन्य स्थानों पर पुलिस संरक्षण में इंटक द्वारा हड़ताल तोड़ने की कार्यवाहियां जारी रहीं. अन्य कोयला खदानों में प्रबन्धकों द्वारा 8 दिनों का वेतन काटने व सेवा में ब्रेक करने की धमकियां दी गयीं और पर्चे बांटे गए. सी आई एल के बहरे प्रबन्धकों ने काम पर आने वाले मजदूरों को खाना देने का भी लालच दिया.

सफलता

ये सब तरीके नाकामयाब रहे. इस्पाती मजदूरों ने सभी दिक्कतों को सामना करते हुए सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल को गौरवमयी सफलता प्रदान की. कोयला क्षेत्रों में इंटक का घटा प्रभाव यह सिद्ध करता है कि नई जे बी सी सी आई बिलकुल बोगस है. अन्य संगठनों के समर्थन से हड़ताल को सफल बनाने में सीटू ने प्रशंसनीय भूमिका अदा की. अखिल भारतीय कोयला मजदूर फेडरेशन के तहत कोलियरी मजदूर सभा आफ इन्डिया, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन, कोयला श्रमिक संघ व अन्य संगठनों ने, संयुक्त संघर्ष समिति ने और राज्य अभियान समितियों ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए. सीटू के उपाध्यक्ष व सांसद मुहम्मद इस्माइल ने सहदोल, कोरबा, बिसरामपुर, सुराकछार, चिरिमिरी, छिदवाड़ा, अमलाई, आदि अनेक कोयला खदानों का दौरा किया. ईस्टर्न कोलफील्ड्स व सिंगारेनी कोयला खदानों में हड़ताल शत प्रतिशत थी. यह बी सी सी एल में 75 प्रतिशत और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स में 60 प्रतिशत रही. हजारीबाग, बुरकुंडा, बर्मो, सौंदा व गिड्डी क्षेत्रों में यह 80 प्रतिशत रही. उड़ीसा की सभी सात खदानों में हड़ताल सफल रही. वेस्टर्न कोलफील्ड्स में यह 60 प्रतिशत रही और खास सफलता वैकुंठपुर, चिरिमिरी, सोहागपुर और छिदवाड़ा क्षेत्रों में मिली. सभी कोयला कम्पनियों व सी आई एल के मुख्यालयों में हड़ताल सम्पूर्ण रही.

एकजुटता कार्यवाहियां

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हैदराबाद सम्मेलन के फैसले के अनुसार देश में मजदूरों के विभिन्न हिस्सों द्वारा एकजुटता कार्यवाहियों की खबरें मिली हैं. सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, बैंक, एल आई सी, रेलवे व सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताली कोयला मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन किए, बिल्ले पहने और संयुक्त रैलियां आयोजित कीं. इस हड़ताल और एकजुटता कार्यवाहियों ने बी पी ई के निर्देशों के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के संघर्ष को एक नया

(शेष पृष्ठ चौदह पर)

अस्पताल व अन्य संस्थान विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की योजना

अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक 3 नवंबर को नयी दिल्ली में संपन्न हुयी. इसमें समूचे देश के अस्पताल, विश्वविद्यालय, कालेज, अनुसंधान व अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

अस्पताल व अन्य संस्थान विधेयक व अन्य तीन काले विधेयकों के खिलाफ समूचे देश में लगातार प्रतिरोध आंदोलन करने के लिए बैठक ने इन संस्थानों के कर्मचारियों को बधाई दी. बैठक ने एकमत से फैसला किया कि राज्य व नगर-स्तरीय सम्मेलन, बैठकें व प्रदर्शन आयोजित करके आंदोलन तेज किया जाए. इसने सरकार से अपील की कि मजदूर वर्ग के साथ, खास तौर से अस्पताल व अन्य संस्थानों के, टकराव से बचने के लिए वह इन विधेयकों को वापस लें.

दिल्ली विश्वविद्यालय व कालेज कर्मचारी आंदोलन

बैठक ने दिल्ली विश्वविद्यालय व कालेज कर्मचारियों को उनके बहादुराना संघर्ष के लिए बधाई देते हुए उनके संघर्ष के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त की और अपनी सभी यूनिटों को आदेश दिया कि वे डीयूसीकेयू की हर संभव मदद करें. कर्मचारी यूनियन (डीयूसीकेयू) के साथ किए गए समझौते को लागू न करने और मनमाने व गैरकानूनी ढंग से कर्मचारियों का दो महीने का वेतन रोकने के लिए बैठक ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों की कड़ी निंदा की. बैठक ने कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन करने के लिए डीयूटीए व डीयूएसयू को बधाई दी. बैठक ने भारत सरकार से मांग की है कि वह जल्दी समझौता कराने के लिए इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें.

बैठक ने चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय के अधिकारियों के दृष्टिकोण की भी कड़ी निंदा की. यहां के कर्मचारी पिछले दो महीनों से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्षरत हैं. बैठक ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे कर्मचारियों की सभी मांगें स्वीकार कर तथा आन्दोलन के दौरान की सभी उत्पीड़न कार्यवाहियां वापस लेकर स्थिति का निपटारा करें. राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्थिति का जायजा लेने के लिए दिसंबर महीने में फिर मिलेगी. □

रेल समाचार

सालाना बैठक के लिए एलआरएसए की तैयारी

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन अपनी सालाना बैठक की तैयारी कर रही है. अभी तक उत्तर पूर्वी जोन (खबर इस अंक में प्रकाशित), पूर्वी जोन (दानापुर, 29-30 सितंबर), केंद्रीय जोन (आमला 5-6 अक्तूबर) पश्चिम जोन (जयपुर, 13-14 अक्तूबर) की सालाना बैठकें हुयी हैं. दक्षिण पूर्वी जोन की बैठक 16-17 दिसंबर को वाल्टेयर में होनी है. इसका उद्घाटन सोमनाथ चटर्जी, सांसद, करेंगे.

इन बैठकों में आयोजकों की उम्मीद से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया. एसोसिएशन के महासचिव एस. के. धर के अनुसार जो इन सभी बैठकों में उपस्थित रहे, पिछली हड़ताल के बाद लोकोकर्मियों के दमन, लगातार उत्पीड़न, कार्यभार में वृद्धि, सख्त-संघर्षों द्वारा अर्जित सुविधाओं की वापसी, ने एकबार फिर रोष पैदा कर दिया है. इसके कारण बहस आमतौर पर आत्मालोचनात्मक रही और चुनाव लगभग एकमत रहे. एआईएलआरएसए को एक बार फिर जुझारू संगठन बनाने के लिए सबकी इच्छा जोर पकड़ रही है.

एआईआरईसी द्वारा एकता के कदम

आल इंडिया रेलवे एंप्लाईज कनफेडरेशन की 4-5 अक्तूबर को सिकंदराबाद में संपन्न वर्किंग कमेटी की बैठक ने रेलकर्मियों की बुनियादी मांगों को मनवाने के लिए एकता की कोशिश में ए. आई आर एफ, आई आर डब्लू एफ, बी आर एसएस व ए आई एल आर एस ए से मिलने का फैसला किया है. ए आई एल आर एस ए ने इसका समर्थन किया है.

समूची रेल प्रणाली के 17 केन्द्रों में सम्मेलन आयोजित करने का वर्किंग कमेटी ने एक कार्यक्रम तैयार किया है ताकि रेल मजदूरों को एस्मा व अन्य चार काले विधेयकों द्वारा उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के बारे में शिक्षित किया जा सके □

दवा उद्योग व भारतीय जनता

बी एस एस आर यूनियन ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 'दवा उद्योग व भारतीय जनता' विषय पर 17 अक्तूबर को एक सम्मेलन आयोजित किया. कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य डा. एस.एम. नवाब ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और डा. बी.एन. दासगुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की. सीटू, किसान सभा व अन्य जन-संगठनों सहित इसमें प्राध्यापकों, वैज्ञानिकों, वकीलों, छात्रों, महिलाओं, आदि ने भाग लिया. यूनियन के महासचिव सी.एस. शर्मा ने की-नोट प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव में दवा उद्योग में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व इजारेदार कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई. □

राज्यों के समाचार

बिहार

जिला व राज्य रैलियां

राज्य अभियान समिति के नेतृत्व में 10 नवम्बर को जिला नुसार रैलियां आयोजित की गईं. कीमतों में वृद्धि, बढ़ती बंदियों तथा तालाबंदियों, बढ़ती बेरोजगारी, कंप्यूट्राइजेशन व मशीनीकरण, एन एस ए, एस्मा, काले विधेयकों, बिहार प्रेस विधेयक, आदि के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर रैलियां आयोजित की गयीं. संघर्ष को तेज करने के लिए एक राज्य-स्तरीय रैली 7 दिसम्बर को होगी. भुरकुन्डा में 23 व 24 अक्टूबर को सम्पन्न राज्य समिति की बैठक में रैलियों की सफलता के लिए तैयारी कदमों पर विचार किया. गया सीटू के कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी, सांसद, ने बैठक में हिस्सा लिया.

परिवहन मजदूरों की हड़ताल

राज्य परिवहन के मजदूरों ने 6 अक्टूबर से अपने 9-सूत्री मांग पत्र के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी. उनकी मांगों में चौथी वेतन कमेटी की रिपोर्ट में असमानताओं का खात्मा, आकस्मिक मजदूरों का स्थायीकरण, बोनस आदि की मांगें शामिल हैं. मांगों पर बात-चीत करने से सरकार इंकार करती रही है. इसने 500 आकस्मिक मजदूरों को हटा दिया है और नेताओं व कार्यकर्त्ताओं पर दमन शुरू कर दिया है. राज्य सीटू के उपाध्यक्ष हरिकृष्ण ने 7 नवम्बर को एक बयान में सरकार की कार्यवाहियों की निंदा की है और तुरन्त समझौते व सभी बर्खास्त मजदूरों की बहाली की मांग की है. उन्होंने मजदूरों के सभी हिस्सों का आह्वान किया है कि वे हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में प्रदर्शन करें.

मंत्रालय अधिकारियों की हड़ताल की तैयारी

बिहार मिनिस्टीरियल आफिसर्ज एसोसिएशन के 9 से 11 अक्टूबर को लाहेरियासराय में सम्पन्न 32वें राज्य सम्मेलन ने कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे चौथी वेतन संशोधन कमेटी की रिपोर्ट में वेतन मागों व अन्य सेवाशर्तों में असमानताओं को खत्म करने की मांग करते हुए हड़ताल करने की तैयारी करें. यदि सरकार मांगें नहीं मानती है तो फिलहाल 16 व 17 दिसम्बर हड़ताल की तारीखें तय की गई हैं. तैयारी आन्दोलन के तौर पर सम्मेलन ने सभी जिलामुख्यालयों में कलेक्टरों के सामने 3 दिसम्बर को प्रदर्शन करने और बाद में 24 घंटे का धरना देने का फैसला लिया है.

सम्मेलन को शुभकामनाएं देते हुए सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने एक संदेश भेजा.

कालीकांत झा, हरिहर प्रसाद सिंह व लल्लू प्रसाद यादव क्रमशः अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष चुने गए. सम्मेलन के अंत में बी एस एस आर यूनियन ने प्रगतिवादी नाटक किए.

रिक्शा मजदूर सभा का 5वां सम्मेलन

रिक्शा मजदूर सभा (सीटू) का पांचवां सम्मेलन बेटैयाह में 17 अक्टूबर को सम्पन्न हुआ. सीटू, एटक, किसान सभा, डी वाई एफ आई के प्रतिनिधियों सहित एक हजार से भी ज्यादा डेलीगेटों, आबजर्वरों व बिरादराना डेलीगेटों ने इसमें भाग लिया. सम्मेलन ने सरकार की कड़ी निंदा की और विशेष इशारा इसके तथाकथित 20-सूत्री कार्यक्रम की ओर था जिसमें रिक्शा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए खास प्रावधान दिए गए हैं. रिक्शा चालकों को मालिक बनाने और उन्हें बीमा व सुरक्षा सुविधा देने के लिए कदम उठाने की बजाए उन्हें पुलिस उदंडता व दमन का शिकार बना दिया गया है. सम्मेलन ने एकता को मजबूत करने तथा सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया. इसमें कीमत वृद्धि, बिहार प्रेस विधेयक व पुलिस दमन के खिलाफ, रिक्शा चालकों के कल्याण के लिए, अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध साजिशों के खिलाफ, आदि, पर प्रस्ताव अपनाए गए. एस.एन. मिश्रा, अध्यक्ष, और कपिलदेव प्रसाद, महासचिव, सहित एक 55-सदस्यीय कमेटी एकमत से चुनी गई. □

उत्तर प्रदेश

संयुक्त आन्दोलन की तैयारी

लखनऊ में 25 अक्टूबर को सम्पन्न राज्य कमेटी की बैठक में केन्द्र व राज्य सरकार के श्रम-विरोधी कदमों के खिलाफ किए गए संघर्षों की समीक्षा की गयी. बिहार प्रेस विधेयक के खिलाफ 18 नवम्बर को लखनऊ में एक गोष्ठी के सम्पन्न होने के बाद आन्दोलन को सभी जिलों व उपमंडल स्तर तक ले जाया जाएगा. ट्रेड यूनियन विरोधी काले विधेयकों के खिलाफ, सेवा सुरक्षा के लिए और 500 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग के लिए संघर्ष तेज करने के लिए इसने 26 दिसम्बर को लखनऊ में राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया.

इसने परिवहन मजदूरों की जायज मांगों के प्रति राज्य सरकार के अड़ियल रवैये की निंदा की. ये मजदूर 9 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं. इसने सभी ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया कि वे संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन करें.

सिनेमा मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

सिनेमा कर्मचारी यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में सिनेमा मजदूरों ने समूचे आजमगढ़ जिले में 10 अक्टूबर से अनिश्चित-कालीन हड़ताल कर दी. वे अपनी 12-सूत्री मांगों पर समझौते की मांग कर रहे हैं, जिनमें सभी बर्खास्त मजदूरों की बहाली, बोनस, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अस्थायी कर्म-चारियों का स्थायीकरण, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन, चिकित्सा सुविधा, छुट्टियों के दिन काम के लिए दोगुना ओवर-टाइम, आदि शामिल हैं, हड़ताल के फलस्वरूप जिले के सभी सिनेमा हाल पूरी तरह बंद हो गए हैं. रैलियां व जनसभाएं लगातार आयोजित की जा रही हैं. □

राजस्थान

सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

दो महीने से भी ज्यादा समय से जयपुर के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. सरकार ने उनकी मांगों पर समझौता करने से इंकार करते हुए उन पर दमन ढाना शुरू कर दिया है. राज्य सीटू के महासचिव ने 11 अक्तूबर को एक बयान में सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की है. उन्होंने सरकार की हरिजनों की दशा में सुधार लाने की तथाकथित घोषणाओं की, जो हरिजन हड़ताली मजदूरों के प्रति इसके रवैये से बेनकाब होती हैं, खिल्ली उड़ाई. उन्होंने मजदूरों के सभी हिस्सों का आह्वान किया कि वे संघर्षरत सफाई कर्म-चारियों को पूरा समर्थन दें और सरकार पर उनकी मांगें मानने के लिए दबाव डालें.

पाली में नयी सीटू यूनियन

विघटनकारियों की सभी घिनौनी चालों को नाकामयाब करते हुए महाराजा श्री उमेद मिल्ज लिमिटेड, पाली, के मजदूरों ने 12 अक्तूबर को एक नयी सीटू यूनियन बनाई और इसका नाम टेक्सटाइल मजदूर एकता यूनियन, पाली, रखा. एक 21 सदस्यीय कमेटी सर्वसम्मति से चुनी गई जिसके पदाधिकारी हैं:- अध्यक्ष : बाबूलाल, उपाध्यक्ष : प्राणनाथ, महासचिव : रामनिवास, संयुक्त सचिव : लक्ष्मण सिंह भाटी, नवरत्न लाल, किशोर सिंह, कोषाध्यक्ष : बाबूलाल शर्मा और संगठन सचिव तुलसी राम.

शाम को एक जनसभा आयोजित की गयी जिसे राज्य सीटू के अध्यक्ष, कृष्णकांत वर्मा, उपाध्यक्ष, डी. डी. शिराली और सचिव अनराज शर्मा ने सम्बोधित किया. वक्ताओं ने निकाले गए पुराने नेतृत्व की व्यक्तिवादी व विघटनकारी भूमिका की निंदा की और मजदूरों का आह्वान किया कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष व सामूहिक कार्य-प्रणाली के लिए कार्य करें. □

मध्य प्रदेश

इन्दौर औद्योगिक क्षेत्र बंद

सुनीता लेबोरेट्रीज के मजदूरों की हड़ताल पर हल करने की मांग करते हुए सीटू के आह्वान पर इन्दौर के 80 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों ने 25 सितंबर को हड़ताल की. चार मजदूरों की बहाली तथा अन्य आर्थिक मांगों जैसे बोनस, मंहगाई भत्ता, आदि, की मांग करते हुए सीटू के नेतृत्व में सुनीता लेबोरेट्रीज के मजदूर 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. सभी गुंडा तरीकों के बावजूद प्रबंधक हड़ताल नहीं तोड़ सके. हड़ताली मजदूरों की मांगों के साथ साथ सीटू ने न्यूनतम वेतन, मंहगाई भत्ते व बोनस के लिए तथा पुलिस दमन, मजदूरों को आतंकित करने के लिए समाजविरोधी तत्वों को लगाने के खिलाफ मांगें भी उठाई. बंद से एक सप्ताह पहले गेट मीटिंगें व जनसभाएं शुरू की गयीं और साथ ही इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के दफ्तर के सामने क्रमिक अनशन शुरू किया गया. इस दफ्तर के सामने शाम को एक भारी सभा की गयी जिसे सीटू नेताओं ने संबोधित किया. बाद में उपश्रमायुक्त को एक ज्ञापन दिया गया.

हीरा मिल्ज में दमन

हीरा मिल्ज (एनटीसी), उज्जैन, के प्रबंधकों ने सीटू के मजदूरों पर भारी दमन शुरू कर दिया है. सीटू के नेतृत्व में मजदूर अपनी मांगों के लिए संघर्षरत थे लेकिन प्रबंधकों ने अल्पसंख्यक इंटक यूनियन के साथ समझौता कर लिया तथा सीटू कार्यकर्त्ताओं पर दमन शुरू कर दिया. कई नेताओं को मुअत्तिल कर दिया गया है. शौचालय जाने के कारण कुछ समय गैरहाजिर रहने तक के कारण भी कुछ को मुअत्तिल कर दिया गया है. इंटक की मदद से भाड़े के गुंडों ने मजदूरों पर खुले-आम हमले शुरू कर दिए हैं. एक मजदूर को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. लेकिन इन सब सीधे हमलों के बावजूद मजदूरों का मनोबल नहीं टूटा और वे अपना संघर्ष जारी किए हुए हैं. □

गुजरात

विशाल कपड़ा सम्मेलन

महा गुजरात मिल मजदूर यूनियन (सीटू) ने 14 सितम्बर को को अहमदाबाद में कपड़ा मजदूरों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया. इसमें 50 मिलों के 1200 डेलीगेटों ने भाग लिया. सीटू के उपाध्यक्ष एस. वाई. कोल्हाटकर ने मजदूरों को बधाई दी कि उन्होंने सहयोगवादी संगठन मजूर महाजन (टीएलए) को अलग करके सीटू की वर्ग संघर्ष की नीति अपनाई है. उन्होंने सरकार की श्रम विरोधी नीतियों पर चर्चा करते हुए मजदूरों का आह्वान किया कि वे अपने हितों व ट्रेडो यूनियन

अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने एकजुट संघर्षों क तेज करें. उन्होंने बंबई के कपड़ा मजदूरों की गौरवमयी हड़ताल का हवाला देते हुए कहा कि उनकी वही समस्याएं हैं जो गुजरात के मजदूरों की हैं और उन्हें बंबई के मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए. यूनियन के सचिव रघुवीर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक के बाद दूसरे मिल से मजदूरों का सीटू को समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है. अहमदाबाद के 63 मिलों में से 50 में अब सीटू का बहुमत है. मजदूरों के हित में सीटू के अथक प्रयास के कारण ही ऐसा संभव हो सका है.

बंबई के कपड़ा मजदूरों के लिए सम्मेलन में 2000 रूपये इकठ्ठा करके एस. वाई. कोल्हाटकर के दिए गए. विभिन्न अन्य संगठनों के बिरादराना डेलीगेटों ने सम्मेलन को शुभकामनाएं दी. सम्मेलन में बंबई कपड़ा हड़ताल के समर्थन में, एन एस ए, एस्मा, काले विधेयकों व बिहार प्रेस विधेयक के खिलाफ, ठेका प्रणाली का खात्मा पर, गुप्त मतदान द्वारा यूनियनों को मान्यता पर, शांति पर, अमरीकी नाभिकीय युद्ध के खिलाफ, आदि पर प्रस्ताव अपनाएं गए.

सीटू यूनियनों की जीत

तीन कपड़ा मिलों में संयुक्त प्रबंधन कांउसिल के लिए सम्पन्न चुनावों में सीटू ने प्रमुख जीतें हासिल की हैं. अरविंद मिल्ज में सीटू के पैनेल ने मजूर महाजन के पांच उम्मीदवारों को 8,000 मतों से हरा दिया. माहेश्वरी मिल्ज में सीटू पैनेल ने मजूर महाजन को 3,000 मतों से हरा दिया. और अशोक मिल में सीटू का एकमात्र उम्मीदवार भी 1,200 मतों से जीता. □

पंजाब

परिवहन मजदूरों का सम्मेलन

सीटू की पंजाब राज्य कमेटी ने 12 नवम्बर को लुधियाना में पंजाब रोड़वेज व पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के मज़दूरों का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया. सम्मेलन में 700 डेलीगेटों ने भाग लिया और गुरुदेव सिंह व सपूरण सिंह ने अध्यक्षता की. अपने उद्घाटन भाषण में पंजाब राज्य सीटू के अध्यक्ष जगजीत सिंह लायलपुरी ने एन एस ए, एस्मा, काले विधेयकों व बी पी ई के निर्देशों आदि जैसे जनवाद-विरोधी व ट्रेड यूनियन-विरोधी कदमों का जिक्र किया तथा उनके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए मजदूरों का आह्वान किया. उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि वे नाभिकीय नरसंहार के खतरे को भी अच्छी तरह समझें और शांति के लिए संघर्ष को तेज करें.

बहस से पता चला कि चालकों व कन्डक्टरों के लिए कोई अनिवार्य बीमा योजना नहीं है. मजदूरों का श्रेणीकरण भी नहीं किया गया है और उनके लिए पदोन्नत्ति नीति भी नहीं है. मंहगाई-भत्ते की प्रणाली गलत है. अनेक मज़दूर 19 जनवरी को हड़ताल पर जाने के कारण अभी तक मुअत्तिल हैं.

एक मांग-पत्र तैयार किया गया. पंजाब सीटू के महासचिव मंगत राम पासला ने राज्य सीटू के तहत इन दो संगठनों की एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा. यह कमेटी मांग-पत्र को अन्तिम रूप देगी तथा संघर्ष का नेतृत्व करेगी. 29 दिसम्बर को मांग दिवस मनाने का सुझाव सर्व-सम्मति से स्वीकार हुआ.

सैशन का समापन करते हुए सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने डेलीगेटों का आह्वान किया कि वे वर्ग-संघर्ष की नीति को बुलंद करें और बताया कि इस द्वारा ही कांग्रेस(आई) के नेतृत्व में अधिनायकवादी ताकतों का कारगर प्रतिरोध किया जा सकता है.

सम्मेलन में गहरी रुचि व संघर्ष की भावना देखी गयी. सीटू का प्रभाव धार्मिक लोगों के बीच बढ़ा है इस बात से प्रदर्शित हुआ कि एक डेलीगेट सम्पूर्ण 'नहंग' के लिबास में था. सम्मेलन को शुभकामनाऐं देते हुए पश्चिम बंगाल के परिवहन मन्त्री व सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य रोबिन मुखर्जी तथा ऑल इन्डिया रोड़ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव सुजीत दास ने संदेश भेजे. □

महाराष्ट्र

खेत मजदूरों का धरना

राज्य के विभिन्न हिस्सों के 1,500 से भी ज्यादा खेत-मज़दूरों ने सितम्बर में हुतात्मा चौक, बम्बई, पर 5 दिन का लगातार धरना दिया. विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से इसका आह्वान 19 सूत्री मांग-पत्र पर जोर देने के लिए किया था. मांगपत्र में श्रेणी-अनुसार 10 से 15 रुपये दैनिक न्यूनतम वेतन, गेहूं का वितरण, मकान स्थल, सस्ता कर्ज, 5 रुपये दैनिक बेरोजगारी भत्ता, मजदूर वर्ग के खिलाफ सभी काले कानूनों की वापसी, आदि, माँगें शामिल हैं. कांग्रेस(आई) नेता की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 6 रुपये से ज्यादा देने से भी सरकार इंकार कर रही है. कुछ इलाकों में तो खेत मज़दूरों को मात्र 2-3 रुपये दैनिक ही मिलते हैं.

धरने को महाराष्ट्र किसान सभा की अध्यक्ष गोदावरी पारुलेकर व महासचिव नरेन्द्र मलुसारे तथा महाराष्ट्र शेत-मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष लहानुकोम, विधायक (सी पी आई-एम), व महासचिव जीवा पंडु गाविट, विधायक (सी पी आई-एम) व अन्यों ने सम्बोधित किया. सीटू के उपाध्यक्ष एस.वाई कोल्हाटकर ने धरने को पहले दिन सम्बोधित किया. ट्रेड यूनियन

संयुक्त संघर्ष समिति के तहत एक मोर्चा धरनास्थल पर अन्तिम दिन गया और खेत-मज़दूरों के साथ मज़दूर वर्ग की एकजुटता व्यक्त की. □

त्रिपुरा

विशाल शांति रैली

त्रिपुरा में 15 अक्तूबर एक स्मरणीय दिन था. समूचे राज्य में भारी शांति रैलियां आयोजित की गयीं. राजधानी अगरतला में दसियों-हजारों शांति प्रेमियों ने पगली-अस्त्र-दौड़ के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद तथा इसके पश्चिमी सहयोगियों की निंदा की. मुख्यमंत्री नृपेन चक्रवर्ती ने पांच कबूतर छोड़ने में पांच बच्चों की सहायता की. उसके बाद मार्च शुरू हुआ. यह एक अद्भुत दृश्य था. नाभिकीय नरसंहार से विश्व को बचाने के लिए जनता के सभी हिस्सों—मजदूरों, किसानों, मंत्रियों, अफसरों, डाक्टरों, नर्सों, छात्रों, अध्यापकों, युवकों, महिलाओं, इंजीनियरों व वकीलों ने शांति-मार्च में हिस्सा लिया. □

कर्नाटक

सीटू नेता की हत्या

मान्यताप्राप्त भारत गोल्डमाइंस यूनियन (सीटू) की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य एम. अरोकियादास की पराजित आर पी आई के नेता के भाड़े के गुंडों ने 30 सितम्बर को छुरा मार कर हत्या कर दी. सीटू यूनियन ने 1980 में बहु-संख्यक यूनियन के चुनाव में विजय हासिल की थी. उसके बाद से हमले हो रहे थे. सीटू यूनियन कार्यालय पर भी हमला हुआ. पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की. अरोकियादास की शवयात्रा में दस हजार से भी ज्यादा मजदूरों, छात्रों व महिलाओं ने हिस्सा लिया. गुंडा हमलों के खिलाफ संघर्ष तेजकर दिया गया है. □

भेल वेतनवार्ताओं में रुकावट

प्रबन्धकों के यह कहने के कारण कि इसके पहले सभी प्रस्ताव तदर्थ हैं और इसके प्रस्तावों को तभी अंतिम माना जाए जब दोनों पार्टियां समझौते पर हस्ताक्षर करने को राजी होंगी, भेल की संयुक्त कमेटी में वेतनवार्ताओं में गम्भीर रुकावट आ गई है.

प्रबन्धकों ने पहले 550 रुपये न्यूनतम बेसिक वेतन तथा 11 व 55 रुपये क्रमशः न्यूनतम व अधिकतम वेतनवृद्धि की दर स्वीकार की थी. इसके आधार पर वेतनमान तय होने थे. लेकिन प्रबन्धकों के अड़ियल रवैये के कारण कि वेतन अंतराल पिछले समझौते के समान ही होने चाहिएं इस विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है. प्रबन्धकों ने ट्रेड यूनियनों के अकुशल मजदूर के लिए 920 रुपये न्यूनतम वेतन तथा 1960 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2 रुपये प्रतिबिन्दु वृद्धि की दर से मंहगाई भत्ते के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. मकान किराया भत्ते के सवाल पर भी अभी कोई समझौता नहीं हो सका.

भेल टाउनशिप में रहने वाले मजदूरों को परिवहन सुविधा की मांग भी अभी मानी नहीं गयी है. कई बार बहस होने के बावजूद स्कूटर भत्ते के सवाल पर कोई फैसला नहीं हुआ है. शिक्षा भत्ते के सवाल पर भी प्रबन्धकों ने ट्रेड यूनियन की यह मांग नहीं मानी है कि समूची फीस प्रबन्धकों द्वारा ही दी जाए.

22-23 अक्टूबर को सम्पन्न संयुक्त कमेटी की इस बैठक में प्रबन्धकों के रवैये के कारण कोई फैसला नहीं हो सका.

इसी दौरान सभी भेल यूनिटों के मजदूर सरकार की वेतनजाम की नीति के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं.

सीटू की तरफ से बैठक में एम.के. पंधे, आर. उमानाथ, भास्कर राव, टी.के. रंगाराजन, सुबैय्याह, राम कृष्णन व राठे ने भाग लिया. □

सफल कोयला हड़ताल

(पृष्ठ नौ से आगे)

मोड़ प्रदान किया है. कोल माइनर्स आफिसर्स एसोसिएशन तक बी पी ए के खिलाफ संघर्ष करने की बात कर रही है. कोयला उद्योग में इंजीनियरों की एसोसिएशन ने पहले ही हड़ताल का समर्थन किया है.

सीटू के महासचिव, पी. राममूर्ति ने 9 नवम्बर को एक बयान में कोयला मजदूरों को उन द्वारा प्रबन्धकों के हड़ताल तोड़ने के सभी गुंडा तरीकों का सामना करते हुए सफल हड़ताल करने के लिए बधाई दी है और उनसे अपील की है कि अपनी एकता को और मजबूत करें तथा अपनी जायज मांगों की प्राप्ति के लिए और भी जुझारू संघर्ष की तैयारी करें.

अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी

एक और बयान में सीटू सचिव तथा अखिल भारतीय कोयला मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष, एम.के. पंधे, ने प्रबन्धकों को चेतावनी दी है कि वे अपनी कोयला खदान मजदूर विरोधी नीति को बदलें और मांगों पर तुरन्त समझौता करें, नहीं तो, कोयला मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे. कोयला यूनियनों की संयुक्त संघर्ष समिति की 22 नवम्बर को एक बैठक कलकत्ता में होगी जिसमें स्थिति का जायजा लिया जाएगा तथा यदि तब तक सरकार व सी आई एल प्रबन्धक मांगों पर समझौता न करें तो कोयला उद्योग में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया जाएगा. □

संक्षिप्त समाचार

भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस विभाग के कोल्ड पिग यार्ड में 531 मज़दूरों में से सीटू यूनियन से सम्बधित 362 को ठेकेदार एस.एस. ...नी ने नौकरी से निकाल दिया है. बाकी मज़दूर इंटक से सम्बंधित थे. प्रबन्धकों व इंटक से सांठ-गांठ करके 15-20 साल से काम कर रहे इन मज़दूरों का ठेकेदार ने अगस्त का वेतन रोक लिया और 13 सितम्बर से गेट-पास देना बंद कर दिया. मज़दूरों ने वेतन की मांग की व इस कार्यवाही का विरोध किया. पुलिस ने 10 अक्टूबर को 143 पुरुष मज़दूरों, 120 महिला मज़दूरों व 106 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया. सहायक श्रमायुक्त के वेतन देने के आदेश का भी प्रबंधकों ने उल्लंघन किया. सभी दमन का सामना करते हुए मज़दूरों ने बहाली व वेतन देने की मांग करते हुए इस्पात भवन पर लगातार धरना शुरू कर दिया है.

* * *

अस्पताल व अन्य संस्थान विधेयक के खिलाफ 20 अक्टूबर को इन्दौर में जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कर्मचारी संघ, एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन व डेली कॉलेज वर्कर्स यूनियन ने एक संयुक्त रैली आयोजित की. इसका आह्वान ऑल इन्डिया यूनिवर्सिटी एम्प्लाईज़ फेडरेशन ने किया था. रैली को सम्बोधित करते हुए ...रशंकर रामदेव ने मज़दूरों का आह्वान किया कि वे जब तक विधेयक वापस नहीं लिया जाता तब तक संघर्ष को आगे बढ़ाएं.

* * *

कर्मचारियों व मज़दूर एसोसिएशनों ने धनबाद जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी ... एन एस ए, एस्मा, औद्योगिक विवाद (संशोधन) कानून व वेतन की अदायगी (संशोधन) कानून, अस्पताल व अन्य संस्थान विधेयक, ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक, बिहार प्रेस विधेयक की वापसी की मांग करते हुए 20 अक्तूबर को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना दिया. मैथों से बोकारो तक 20 यूनियनों के 200 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और युद्ध के खतरे के खिलाफ भी इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की. कमेटी के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार, आई.डी. सिंह व यू.एस. चन्दा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिया. सीटू के जी.के. बक्शी ने धरने को बधाई दी.

* * *

ऑल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की उत्तर-पूर्वी रेलवे की इज्जतनगर डिविज़न का 8वां सालाना सम्मेलन 23 सितम्बर को बरेली में सम्पन्न हुआ. इसमें 115 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, शारदा प्रसाद मिश्रा व जे.के. सक्सेना क्रमशः अध्यक्ष व सचिव चुने गए. इसके बाद जोनल सम्मेलन 24 व 25 सितम्बर को हुआ जिसमें 395 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसके बाद एक रैली हुई जिसे सीटू की उ.प्र. राज्य कमेटी के अध्यक्ष हर सहाय सिंह ने सम्बोधित किया. इसने एन एस ए, एस्मा, काले विधेयकों व बिहार प्रेस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव अपनाए और रेलकर्मियों की मांगों पर समझौता व उत्पीड़न के कदमों की वापसी की मांग की.

* * *

धारा 144 की परवाह नहीं करते हुए सैंकड़ों म्यूनिसिपल मज़दूरों ने 12 नवम्बर को दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय टाऊन हॉल के सामने म्यूनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन (सीटू) के आह्वान पर अपने 22-सूत्री मांग-पत्र, जिसे अगस्त में दायर किया गया था, पर समझौते की माँग करते हुए प्रदर्शन किया. उनकी एक मांग 500 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन की भी है. यूनियन के अध्यक्ष चाचा शादीराम व महासचिव बच्चन सिंह ने उन्हें सम्बोधित किया.

* * *

मारवाड़ी औषधालय कर्मचारी यूनियन (सीटू), दिल्ली, ने अपने लम्बे संघर्ष के द्वारा प्रबन्धकों को मांग पत्र पर समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया. समझौते के तहत मजदूरों के वेतन में 1 जुलाई से 13 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है. इसके अलावा 1 जनवरी 1983 के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के मज़दूरों से वेतन में क्रमशः 6 व 4 प्रतिशत वृद्धि होगी.

* * *

भारत स्टील ट्यूब्स कम्पनी, गन्नौर (हरियाणा) के मजदूर बोनस के लिए और प्रबन्धकों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्षरत हैं. प्रबन्धकों ने चार यूनियन नेताओं को इस तर्क से मुअत्तिल कर दिया कि उन्होंने मज़दूरों को एक ऐसे दिन गैरहाजिर होने के लिए उकसाया जिसे हरियाणा सरकार ने एन.आई. कानून के तहत छुट्टी का दिन घोषित किया था. 21 अक्तूबर को एक जन-सभा में सी पी आई(एम) के सांसदों बसुदेव आचार्य व मसुदल हुसैन ने मज़दूरों को सम्बोधित करते हुए उनकी मांगों का समर्थन किया. जब उन्होंने सूखा-पीड़ित पश्चिम बंगाल के मज़दूरों के हालात का ब्यौरा दिया तो मज़दूरों ने उसी समय 101 रुपये इकट्ठा करके मुख्य मन्त्री सहायता कोष के लिए दिया. □

संपादक मंडल

बी.टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम.के. पंधे (संपादक)

युद्ध के खिलाफ एक सितंबर को शांति रैलियां

ग्रेट ब्रिटेन : शांति मार्च के अंत के दिन एडिनबर्ग में एक प्रदर्शन में क्लाइड में ब्रिटिश नाभिकीय नेवल अड्डे, फास्लेन, पर एक स्थायी शांति शिविर स्थापित करने का फैसला लिया गया.

पश्चिम जर्मनी : डी जी बी क्षेत्रीय संगठनों ने पश्चिम बर्लिन, सारब्रूकेन, हर्न, व अन्य नगरों में शांति प्रदर्शन आयोजित किए.

अमरीका : भारी रैलियां आयोजित की गईं. इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ मकेनिस्ट्स ने नाभिकीय नरसंहार के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए एक घोषणा जारी की. श्रम दिवस 6 सितंबर को भी अमरीका में रैलियां व प्रदर्शन किए गए. 'संघर्ष सप्ताह' के दौरान कई सामाजिक संगठनों ने नाभिकीय युद्ध के खिलाफ वाशिंगटन में सीटल स्थल पर एक गोष्ठी आयोजित की. इसने घोषणा की कि वाशिंगटन का नाभिकीय युद्ध में अस्तित्व या जीत का विश्वास बेतुका है. सीटल में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है जिसे बाद में ताशकंद (सोवियत संघ) भेज दिया जाएगा ताकि दो देशों की जनता एकजुट होकर युद्ध के खतरे के खात्मे के लिए संघर्ष करें.

जापान : देश का मिलिटरी बजट कम कराने के लिए जापानी ट्रेड यूनियनों ने अभियान शुरू कर दिया है. यह नवंबर तक जारी रहेगा.

फ्रांस : अनेक प्रदर्शन व सभाएं आयोजित की गईं जिनमें सीजीटी ने मजदूरों को बताया कि युद्ध के खतरे को खत्म किए बिना बेहतर जीवन के लिए संघर्ष असंभव है.

ग्रीस : ट्रेड यूनियनों ने एथेंस, पिराउस व विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जन प्रदर्शन व रैलियां आयोजित कीं.

डेनमार्क : कापेनहागेन व अन्य शहरों में स्किल्ड वर्कर्स यूनियन, सेंट्रल फेडरेशन आफ यंग वर्कर्स व अन्य संगठनों ने जनसभाएं व प्रदर्शन आयोजित किए.

आस्ट्रिया : आस्ट्रियन ट्रेड यूनियन कनफेडरेशन ने सभी प्रमुख नगरों व प्रतिष्ठानों में सभाएं, प्रदर्शन व कार्यशालाएं आयोजित कीं.

नार्वे : दो हजार मजदूरों ने स्टावेंगर से सन्नेज तक मार्च किया. रास्ते में उन्होंने सुला हवाई अड्डे पर प्रदर्शन किया जिसे अमरीका व नाटो ने 'संकट' के समय में प्रमुख भूमिका के लिए आरक्षित कर रखा है. प्रदर्शनकारी यह नारा लगा रहे थे : "सुला में नाभिकीय बांबर नहीं."

पुर्तगाल : लगभग सभी स्थानों पर सभाएं व प्रदर्शन आयोजित किये गये. ट्रेड यूनियनों ने अमरीका की इस द्वा अंतर्राष्ट्रीय तनाव पैदा करने के लिए निंदा करते हुए एव घोषणा प्रकाशित की.

मोंगोलिया : उलन बातौर में ट्रेड यूनियन रैली ने सोवि संघ के शांति प्रयासों का समर्थन किया और अमरीका की द दौड़ के लिए निंदा की.

अफगानिस्तान : अफगानिस्तान सेंट्रल ब्यूरो आफ ले यूनियंस ने प्रतिष्ठानों में जन प्रदर्शन व सभाएं आयोजित रेडियो, टेलीविजन व अन्य जनप्रसारण के साधनों द्वारा व्या अभियान शुरू किया गया है.

उगांडा : कपड़ा मजदूरों, दर्जियों की यूनियन व अन्य अमरीका की जंगबाजी के खिलाफ शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का समर्थन किया.

मदागास्कर : शांति के लिए संघर्ष के प्रति संकल्प हुए ट्रेड यूनियनों ने मजदूर रैलियां व प्रदर्शन आयोजित दक्षिण-पूर्वी पैसिफिक की ट्रेड यूनियनों ने 26 से 28 सित को न्यू कालेडोमा में शांति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजि करने का फैसला किया.

पूर्वी जर्मनी : एफ डी जी बी द्वारा बर्लिन में एक भ रैली आयोजित की गयी. शांति के लिए संघर्ष के प्रति सक व्यक्त करते हुए सभी प्रतिष्ठानों में सभाएं की गयीं.

बुलगारिया : सोफिया में बुलगेरियन ट्रेड यूनियन सेंट्रल कमेटी ने मजदूरों की एक भारी रैली आयोजित की. रेडियो व टेलीविजन द्वारा शांति अभियान शुरू किया गया.

हंगरी : समूचे देश में सभी प्रतिष्ठानों में ट्रेड यूनियनों ने रैलियां व सभाएं आयोजित कीं. मेन स्कूल आफ ट्रेड यूनियन स्टडीज में एक विशेष बैठक आयोजित की गयी.

सोवियत संघ : मास्को व सोवियत संघ के अन्य म शहरों में शांति दिवस के दिन मजदूरों की भारी रैलिया हुइ देश के सभी प्रतिष्ठानों में सभाएं, रैलियां व प्रदर्शन आयोजि किये गये.

सीटू नामांकन

यूगोस्लाविया की कनफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंज की बेल्ग्रेद में 11 से 15 नवम्बर को होने वाली 9वीं कांग्रेस भाग लेने के लिए सीटू ने केरल राज्य कमेटी के मह सचिव ए एन. रवीन्द्रनाथ को नामांकित किया है.

एम.के. पंधे द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेड्स, ओखला फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित.